वाल्मीकि बस्ती में भी पहुँचा पानी

करनाल, (जेके शर्मा) : आख़िरकार नगर निगम करनाल ने वाल्मीकि कॉलोनी में भी पानी पहुँचाने की पहल कर दी है।

वार्ड-16 के तहत हांसी रोड स्थित वाल्मिकी कॉलोनी में मेयर रेणूबाला गुप्ता ने पार्षद रजनी परोचा की मौजूदगी में पेयजल आपूर्ति के लिए लगाए जाने वाले नलकूप के काम की शुरूआत की। इस पर अनुमानित 17 लाख रूपये खर्च होंगे।

मेयर ने बताया कि वाल्मिकी कॉलोनी में पहले अस्थाई ट्यूबवेल था। यहां के निवासियों की मांग थी कि उन्हें ट्यूबवेल की पक्की व्यवस्था करवाई जाए। वार्ड-16 की पार्षद रजनी परोचा ने इस अवसर पर नए ट्यूबवेल का निर्माण करवाने के लिए महापौर का धन्यवाद किया। उनके साथ इस मौक़े पर यशपाल वर्मा, दीपक, बलविन्द्र, रजत, संतराम, सतपाल, पवन आदि मौजूद थे।

रेकॉर्ड टैक्स वसूली की तारीफ

करनाल, (म.मो) : प्रदेश के अर्बन लोकल बॉडी निदेशक अशोक मीणा ने बुधवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाय कार्यालयों की कारगुजारी की समीक्षा करते हुए करनाल नगर निगम के आयुक्त विक्रम की प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी को लेकर सराहना की और कहा कि दूसरे निगमों के आयुक्त व नगर पालिका सचिव इनका अनुकरण करें।

निदेशक ने कहा कि जिन-जिन सरकारी विभागों का प्रॉपर्टी टैक्स लंबित है, उनकी सूची यूएलबी को भेजें। सीएम विंडो पर आई शिकायतों के उचित समय पर निस्तारण के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करें। इसके अतिरिक्त नगर निगम से जुड़े जिन बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, आयुक्त खुद उनकी क्वालिटी चेक करें। ऐसे प्रोजेक्टों पर सरकार की बड़ी राशि खर्च होती है।

करनाल जिला बार संघ का शपथ ग्रहण

करनाल(म.मो.) बुधवार को जिला बार संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। वरिष्ठ वकीलों ने नए प्रधान कंवरप्रीत सिंह भाटिया, उपप्रधान हरीश आर्य, सचिव सुमित मोहन शर्मा, संयुक्त सचिव सुनील समाना व कोषाध्यक्ष तपन वर्मा को शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधान कंवरप्रीत सिंह ने कहा कि वकीलों की समस्याओं को हल करने के लिए जिला बार संघ प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेगा।

इस अवसर पर जगमाल जटैन, महेन्द्र सलूजा, युद्धवीर चौहान, पवन गहलोत, जयपाल कश्यप, सतपाल चोपड़ा, डीएस मान, आरआर शर्मा, वीरेंद्र पहल, चांदवीर मढाण, निर्मल जीत विर्क व मनीष लाठर आदि मौजूद थे।

समस्त करनाल वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

ईश गुलाटी
करनाल नगर निगम
पार्षद वार्ड नंबर 13

क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान (आरएलआई) में कुछ कर्मचारी आते हैं केवल आराम फरमाने

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: केंद्र सरकार के नियंत्रण में चलने वाले फरीदाबाद के क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान (रीजनल लेबर इंस्टियूट-आरएलआई) का इन दिनों जो हाल है, उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। देश में फरीदाबाद के अलावा कानपुर, शिलान्ग, चेन्नै में ही आरएलआई है। इन्हें विशेषकर औद्योगिक सुरक्षा, कारखानों में सफाई, केमिकल इंडस्ट्री पर विशेष नजर और बड़े हादसे होने पर उसे नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया है। फरीदाबाद का आरएलआई फरवरी 2009 में खुला। इसके तहत दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आते हैं। यानी आरएलआई फरीदाबाद का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है।

इसी सेंटर के किसी कर्मचारी ने जो फोटो भेजी है, उससे फरीदाबाद सेन्टर की असलियत सामने आ गई है। फोटो में दिखाई दे रहा है कि आरएलआई फरीदाबाद में बतौर सुपरवाइजर तैनात गोविन्द शर्मा हर समय आराम की मुद्रा में नजर आते हैं। कई बार वह दफ्तर के लान में तो कई बार दफ्तर की बड़ी टेबल पर ही पसर जाते हैं। यहां चंद कर्मचारी दफ्तर में बैठकर हर समय तंबाकू बनाने और बातचीत में व्यस्त रहते हैं। इन चंद कर्मचारियों ने अपने सुपरवाइजर को देखकर यह सब शुरू किया है।

हालांकि दफ्तर में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आरएलआई फरीदाबाद को बुलंदियों पर ले जाने के लिए दिन-रात काम में जुटा रहता है। लेकिन सुपरवाइजर गोविन्द शर्मा अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। जिस कर्मचारी ने सुपरवाइजर गोविन्द शर्मा का सोते हुए फोटो खींचा है, उसकी कॉपी केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केन्द्रीय मंत्रियों को भेजी है। यह समाचार लिखे जाने तक गोविन्द शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका खुलासा केन्द्र सरकार ने नहीं किया है।

29 चौराहों पर सीसीटीवी का काम इसी महीने होगा पूरा

करनाल, (म.मो): शहर में 29 चौक-चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का काम नवंबर अंत तक मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी ओर इससे जुड़े स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आई.सी.सी.सी. (इंटाग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) के मुकम्मल होने में भी अब ज्यादा समय नहीं, अगले माह दिसम्बर मध्य में यह यह पूरी तरह से काम करने लगेगा।

बुधवार को डॉ. मंगलसेन ऑडिटोरियम में इस प्रोजेक्ट को लेकर की गई समीक्षा बैठक में उपायुक्त एवं करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ निशांत कुमार यादव ने यह जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए सम्बंधित कम्पनी की ओर से पोल लगा दिए गए हैं, जिनपर निगरानी करने वाले अलग-अलग कैमरे लगेंगे। इनमें 100 बूलेट कैमरे, 50 फिक्स, चारों तरफ घूमने वाले 50 कैमरे और ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए भी 29 कैमरे रहेंगे। सड़क पर चलते, चौक की क्रॉसिंग के दौरान नम्बर प्लेट चेक करने वाले कैमरो की संख्या 95 बताई गई है। जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन करेगा, यह कैमरे उसकी गलती को कैप्चर करके आई.सी.सी.सी. व ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे सम्बंधित वाहन चालक को आनलाइन चालान जारी होगा। इस व्यवस्था से ट्रैफिक नियमो का पालन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पावर सप्लाई के लिए लगेंगे ट्रांसफार्मर व जेनसेट-सेंटर में पावर सप्लाई को रेगूलर रखने के लिए ट्रांसफार्मर और जेनसेट दोनो की व्यवस्था की जा रही है। जेनसेट के लिए जगह का चयन कर लिया गया है, जबकि ट्रांसफ़ॉर्मर भी इसी सप्ताह लग जाएगा, इसकी तैयारी हो गई है। बैठक में अधीक्षण अभियंता दीपक किंगर, इंजीनियर मोहन शर्मा, पीएमसी प्रवीन झा और उनकी टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

लखानी शू कंपनी ने बोनस हड़पा...

पेज एक का शेष

मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने पुलिस को पैसे देकर अपने पक्ष में भारी संख्या में बुला लिया और पुलिस लाठीचार्ज कर मजदूरों पर दबाव बनाना चाहती है। क्योंकि महिला कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है इसलिए पुलिस मजबूरन ऐसा नहीं कर पा रही।

जबकि पुलिस ने बताया कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर बनाये रखने की ड्यूटी दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल कंपनी के भीतर डट गया है ताकि मजदूरों पर दबाव बन सके।

कंपनी में चार साल से काम कर रहे मौसम सिंह ने बताया कि कोरोना के नाम पर बिना नोटिस बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके बावजूद कर्मचारियों ने कोई हंगामा नहीं किया। पर अब कर्मचारी पिछले साल का बोनस भी न पायें तो यह तो अन्याय है। कंपनी ने कोरोना का बहाना करके अगर इस साल का बोनस नहीं दिया तो एक बार समझा जा सकता है पर ये मांग पिछले साल के बोनस के लिए है।

कंपनी में ही काम करने वाले संजय की नाराजगी कंपनी द्वारा कर्मचारियों के साथ की जाने वाली वादाखिलाफी से है। उन्होंने बताया कि पिछले साल एडीडास नामक बड़ी कंपनी से लखानी को ऑर्डर मिला और लखानी को एडीडास ने पूरा पेमेंट भी कर दिया है। इसके बावजूद अब लखानी मजदूरों के नाम का पैसा लेकर भी उनको उनका पैसा नहीं दे रही है। जबकि वर्कआर्डर और बोनस दोनों ही पिछले साल का है। कोरोना तो मार्च से आया है जिससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है।

प्रबंधकों ने एक अन्य न्यूज चैनल को बताया है कि क्योंकि कंपनी को बीते वर्ष मुनाफा नहीं हुआ है फिर भी कंपनी 8.33 प्रतिशत के बोनस को 10 प्रतिशत करके दे रही है।। इस मामले में बैलेंस शीट लेबर विभाग को कल दिखा दी जाएगी।

फिलहाल कर्मचारी प्रबंधन की इस दलील को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बोनस से लेबर विभाग का कोई सरोकार नहीं है। कुछ का मानना है कि सरकारी तंत्र भी इन्ही पूंजीपतियों की जेब में बैठ कर उन्ही की भाषा बोलता है सो उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं। देव ने बताया कि मजदूरों में फूट डालने के लिए कंपनी ने फेक्टरी परिसर के अन्दर रह गए मजदूरों को कहा कि जो बाहर हैं अब वो बाहर ही होंगे और जो भीतर हैं वो भीतर। मतलब जिसको काम करना है वो अपनी नौकरी बचाये रखने के लिए बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का साथ न दे।

फिलहाल खबर लिखे जाने तक मजदूर एकजुट होकर अपनी माँग पर अड़े हुए हैं और कंपनी गेट पर बड़ी संख्या में जुट कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की खास बात ये है कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि किसी प्रकार की यूनियन इसमें शामिल नहीं थी, फिलहाल कई मजदूर संगठनों ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए इसमें शिरकत भी की है।